

छत्तीसगढ़ ने वन-क्लक सगिल वड्डो ससिस्टम 2.0 लॉन्च किया

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रायपुर में “वन-क्लक सगिल वड्डो ससिस्टम 2.0” लॉन्च किया, इसे राज्य को [सेमीकंडक्टर](#), [AI](#), फार्मा, रक्षा और [ग्रीन हाइड्रोजन](#) जैसे उभरते उद्योगों का केंद्र बनाने की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

मुख्य बिंदु

- **वन-क्लक सगिल वड्डो ससिस्टम 2.0:**
 - यह ऑनलाइन आवेदन, वभागीय मंजूरी और सब्सिडी प्रसंस्करण को एकीकृत करता है।
 - यह प्रणाली उद्योग स्थापित करने के लिये पारदर्शी और वास्तविक समय पर अनुमोदन सुनिश्चित करती है।
- **नई औद्योगिक नीति:**
 - छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में [रोज़गार](#) सृजन और आर्थिक समृद्धि को प्राथमिकता दी गई है।
 - 11 कंपनियों द्वारा प्रस्तुत 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों से 20,000 से अधिक युवा लाभान्वित होंगे।
 - एक सरकारी बयान के अनुसार, छत्तीसगढ़ को **5.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।**
 - **वर्ष 2025 में भारत के कुल निवेश प्रवाह में राज्य का योगदान 3.71% होगा**, जो इसके बढ़ते औद्योगिक आकर्षण को दर्शाता है।
- **छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2025:**
 - मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंजूरी देने की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य राज्य को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स हब बनाना है।
 - यह नीति वैश्विक और घरेलू लॉजिस्टिक्स कंपनियों को आकर्षित करेगी, निर्यात बुनियादी ढाँचे में सुधार करेगी और उद्योगों और किसानों के लिये कफायती भंडारण सुनिश्चित करेगी।
- **महत्त्व:**
 - उन्नत औद्योगिक विकास: वन-क्लक सगिल वड्डो ससिस्टम 2.0 निवेशकों को आकर्षित करना जारी रखेगा और औद्योगिक स्थापना प्रक्रिया में तेजी लाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ की प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थिति मजबूत होगी।
 - उभरते क्षेत्रों में निवेश: प्रमुख क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर केंद्रित प्रयास राज्य को भविष्य में मुख्य अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद करेंगे।
 - लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढाँचे का विकास: लॉजिस्टिक्स नीति राज्य की निर्यात क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ भारत के लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण राज्य बन जाएगा।
 - रोज़गार सृजन और आर्थिक समृद्धि: बड़े निवेश और बढ़ते औद्योगिक आधार के साथ, राज्य हजारों रोज़गार अवसरों का सृजन करेगा, जिससे इसके निवासियों के लिये आर्थिक समृद्धि आएगी।

हरित हाइड्रोजन

- हाइड्रोजन एक प्रमुख औद्योगिक ईंधन है, जिसका उपयोग अमोनिया (एक प्रमुख उर्वरक), इस्पात, रफ़ाइनरियों और वलियुत उत्पादन सहित **वभिन्न प्रकार के कार्यों** में किया जाता है।
- हालाँकि, अब निर्मित सभी हाइड्रोजन को **तथाकथित ब्लैक या ब्राउन** हाइड्रोजन कहा जाता है, क्योंकि वे कोयले से उत्पादित होते हैं।
- हाइड्रोजन **ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है**। लेकिन शुद्ध, या मौलिक हाइड्रोजन, बहुत दुर्लभ है।
 - यह लगभग हमेशा ही ऑक्सीजन के साथ मलिकर जल बनाने वाले योगिकों में मौजूद रहता है।
- लेकिन जब वलियुत धारा को पानी से गुजारा जाता है, तो यह **इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से इसे मौलिक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में वभाजित कर देता है**।

- और यदि इस प्रक्रिया के लिये उपयोग की जाने वाली बजिली पवन या सौर जैसे नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त होती है तो इस प्रकार उत्पादित हाइड्रोजन को **ग्रीन हाइड्रोजन** कहा जाता है।
- हाइड्रोजन से जुड़े रंग हाइड्रोजन अणु को उत्पन्न करने के लिये पर्युक्त वदियुत के स्रोत को इंगति करते हैं।
 - उदाहरण के लिये, यदिकोयले का उपयोग किया जाता है, तो इसे ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है।

अर्द्धचालक (SEMICONDUCTORS)

अर्द्धचालक/सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता या चालकता धातुओं तथा विद्युतरोधी पदार्थों के बीच की होती है।



उदाहरण

- तत्व: सिलिकॉन और जर्मेनियम
- यौगिक: गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सेलेनाइड

महत्त्व

- अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों के लिये आवश्यक - एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, संचार, स्वच्छ ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और चिकित्सा उपकरण आदि।

सेमीकंडक्टर और भारत

- प्रमुख निर्यातक देश: चीन, ताइवान, अमेरिका और जापान
- भारत का सेमीकंडक्टर बाज़ार: वर्ष 2026 तक 55 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है

योजनाएँ

- उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना
- डिज़ाइन संबद्ध प्रोत्साहन (DLI) योजना
- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्द्धचालकों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना (SPECS)

उद्देश्य

- देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण को प्रोत्साहित करना।
- सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में >20 घरेलू कंपनियों का पोषण आगामी 5 वर्षों में > 1500 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल करना
- इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों और अर्द्धचालकों का निर्माण

भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)

उद्देश्य

- अर्द्धचालक, डिस्प्ले विनिर्माण और डिज़ाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना

आरंभ

- 2021

नोडल मंत्रालय

- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

कुल वित्तीय परिव्यय

- 76,000 करोड़ रुपये

घटक

- भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिये योजना
- भारत में डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिये योजना
- भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एवं पैकेजिंग (ATMP)/OSAT सुविधाओं की स्थापना के लिये योजना
- DLI योजना

